समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देकर उन के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें उचित मुआवजा जल्दी मिल सके।

(vii) *Need to resettle the peasant families affected by construction of Kallada Dam in Kerala.*

SHRI P. K. KODIYAN (ADOOR) Sir, under rule 377, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance with the hope that he would take immediate action thereon.

Kallada irrigation project is one of the major irrigation projects of Kerala. The main dam of the project, the Kallada Dam, is being constructed at Thenmala in my constituency and is nearing completion. Nearly 200 peasant families who are living in the catchment area of the project have to be resettled.

The Kerala Government has decided to provide the peasants with alternative land in Kulathupuzha village in Pathanapuram taluk. After a series of conferences held to discuss the settlement problem, it was finally decided to allot nearly 350 acres of land to the peasants to be evicted from the catchment areas. It was also decided that these 350 acres of land would be taken from 10,000 acres of forest land allotted for oil palm planatation. Most of this forest land was already cleared.

In spite of this firm decision, the peasants are now told that the Government of India's clearance is needed for implementing this decision. I understood that the State Government has already sought the Centre's clearance for settlement of the peasants on the above-mentioned land.

The peasants are very much upset and worried over the uncertainty of their future due to the delay in assignment of land to them. I would request the hon. Minister to kindly give approval to the proposal of the State Government, so that the peasants are settled as soon as they are evicted from the catchment area.

(viii) *Development of Pilibhit and Puwayan Tehsil of Shahjhanpur district in Uttar Pradesh.*

श्री हरीश कुमार गंगावर (पीलीभीत): मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पीलीभीत का पूरा जिला व शाहजहांपुर की पुवायां तहसील शामिल है। यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। पीलीभीत तो छोटी लाइन से जुड़ा भी है परन्तु पुवायां क्षेत्र के दोनों ओर 50-50 किलोमीटर तक कोई रेलवे लाइन भी नहीं है। सिवाय पीलीभीत जिले के दो स्थानों पर चीनी मिलों के और कोई भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ा उद्योग नहीं है। नेपाल व उसके द्वारा तिब्बत से मिला होने के कारण इस क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है और बड़े उद्योगों की स्थापना द्वारा इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। गेहूं, धान, गन्ना की उपज के लिए यह क्षेत्र विख्यात है। परन्तु इनसे सम्बन्धित उद्योग धन्धों का अभाव है। सरकार ने इस जिले को उद्योग धन्धों में विशेष अनुदान देने वाले जिलों में भी नहीं चुना है। अतः उसकी आर्थिक व औद्योगिक उन्नति होना निकट भविष्य में संभव नहीं है। पुवायां में एक सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी समय पहले कर रखा है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उसका लाइसेंस जारी नहीं किया है। इस क्षेत्र की जनता की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और बेरोजगारी सीमा से अधिक है। वन-संपत्ति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में कागज का कारखाना आसानी से लगाया जा सकता है। लघु व बड़े उद्योगों द्वारा इस क्षेत्र की जनता को गरीबी भी जा सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में लघु व बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक पग तुरन्त उठाए और लघु उद्योगों में विशेष रियायत व अनुदान के क्षेत्र में शामिल कराये।

(ix) *Need to introduce high speed small ships on Konkan service of Mogul lines.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Bapusaheb Parulekar. He will be followed by Shri Somnath Chatterjee. He will be the last speaker for today.